दिल्ली स्थित औद्योगिक एककों के प्रशासनिक कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण

2081. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नियंत्रण में संचालित ऐसे औद्योगिक एककों के कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं जिनके उत्पादन एकक दिल्ली से बाहर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन कार्यालयों के स्थानान्तरण को स्वीकार किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इनका अब तक स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इन कार्यालयों के स्थानान्तरण के लिए कोई अंतिम अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) सम्भवत: माननीय सदस्यों का आशय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों से है। ऐसे लगभग 180 कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय / सम्पर्क / शाखा कार्यालय हैं। इनमें से कई उपक्रमों की उत्पादन परियोजनायें दिल्ली से बाहर स्थित हैं।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कागज की कीमतों में भारी वृद्धि

2082. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पादन एककों द्वारा कागज की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कागज की कीमतों में कितनी वृद्धि की गई और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कागज की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) उद्योग द्वारा विभिन्न किस्मों के कागज और गत्ते का उत्पादन तथा विपणन किया जाता है और उनके मूल्य एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान,विभिन्न किस्मों के कागज़ और गत्ते के कारखाना मूल्य में वृद्धि के विषय में समाचार आते रहे हैं तथा यह मूल्य वृद्धि एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भिन्न भिन्न है। निवेशों की लागत किराये भाड़े, उत्पादन कर, इत्यादि में वृद्धि के कारण मूल्यों में यथासूचित संशोधन आवश्यक हो गया है।

(ग) इस समय, देश में कागज के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। सरकार द्वारा कागज और गत्ते के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप, जहां तक कागज़ की सामान्य किस्मों का संबंध है, देश लगभग आत्म निर्भर हो गया है।

Supreme Court Directions on recovery from DPEA

2083. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what was the direction of the Supreme Court on the issue of recovery from DPEA in respect to bulk drugs and formulations;

(b) whether it was on bulk drugs or formulations;

(c) whether it is a fact that special team calculated on bulk drugs;

(d) if so, on whose directive; and